जबलपुर | मंगलवार । 14 अप्रैल 2026 । वर्ष 77 । अंक 81 । पृष्ठ 12 । मूल्य रु. 5.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

अंबेडकर जयंती

5 मुझे आप पर भरोसा नहीं : केजरीवाल

6 भारत-अमेरिकी संबंधों में प्रगति के प्रयास

7 ड्रोन तकनीक में भारत-यूके का बड़ा कदम

8 सिनर ने अल्काराज को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स जीता

महिलाएं करेंगी लोकतंत्र मजबूत

संसद एक नया इतिहास रचने के करीब : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, 13 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान महिलाओं की भूमिका, प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण को लेकर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया. उन्होंने देशभर की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक नारी शक्ति को समर्पित फैसले की ओर बढ़ रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, जो सामाजिक न्याय और समानता को नई दिशा देगा. उन्होंने बताया कि 2023 में नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पहला कदम उठाया गया था और अब इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है. 16 अप्रैल से संसद के विशेष सत्र में इस पर व्यापक चर्चा होगी.

महिलाओं से सक्रिय भागीदारी की अपील

प्रधानमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं. अपने सांसदों से संवाद करें और इस विषय को गांव-गांव तक पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश और सभी राजनीतिक दलों का सामूहिक प्रयास है. उन्होंने बताया कि भारत में पंचायत से लेकर उच्च पदों तक महिलाओं ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है. वर्तमान में लाखों महिलाएं स्थानीय निकायों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और कई राज्यों में उनकी भागीदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी दलों के सहयोग से यह अधिनियम पारित हुआ था और अब इसे लागू करना प्राथमिकता है, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा.

संसद में 16 से विशेष सत्र भी होगा

महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का एक सत्र बुलाया जा रहा है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं के लिए आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन (सीमांकन) से जोड़ दिया था.

2 बड़े संशोधन की प्लानिंग

सरकार ने दो बड़े संशोधनों की योजना बनाई है, जिसमें एक अलग परिसीमन विधेयक भी शामिल है. महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तय करने के लिए इन दोनों विधेयकों को संवैधानिक संशोधन के तौर पर पारित किया जाना जरूरी है.

प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड और यूपी का दौरा आज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे. इस दौरान वे कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन प्रमुख है. प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11.15 बजे सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे के ऊंचे खंड पर बने वन्यजीव गलियारे का दौरा और समीक्षा करेंगे. यह गलियारा मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. इसके बाद प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचकर जय मां दात काली मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे. यह मंदिर क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है.

लापरवाही के आरोप में एसडीएम को हटाया

दतिया. गंभीर लापरवाही के आरोप में कलेक्टर ने दतिया के एसडीएम संतोष तिवारी को हटा दिया है. जिले में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है. संयुक्त कलेक्टर लोकेंद्र सरल को एसडीएम की नई जिम्मेदारी सौंपी है. लापरवाही की शिकायत के चलते कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने दतिया अनुभाग के एसडीएम के दायित्व में यह बड़ा बदलाव किया है. अभी कुछ और प्रशासनिक परिवर्तन हो सकते हैं.

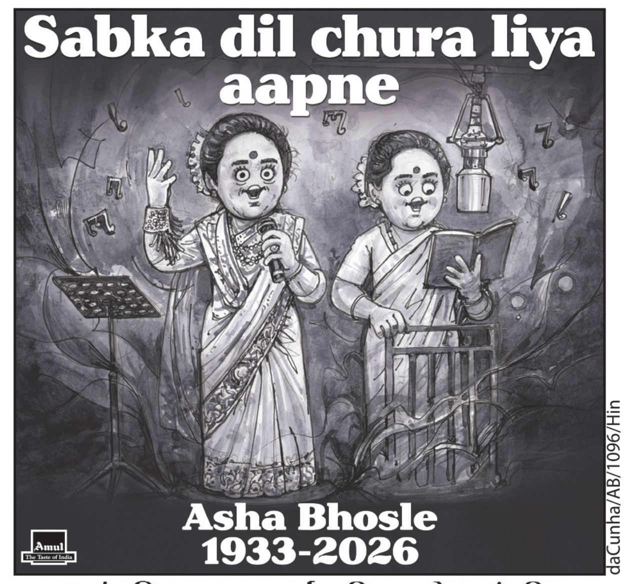

अत्यंत प्रिय, महान पार्श्व गायिका को श्रद्धांजलि!

अमेरिका ने की हार्मूज की नाकेबंदी

दुनियाभर में आपूर्ति श्रृंखला पर मंडरा रहा गहरा संकट

वॉशिंगटन, 13 अप्रैल. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ परमाणु वार्ता विफल होने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नौसेना द्वारा तत्काल नाकेबंदी की घोषणा की है. इस कदम का उद्देश्य ईरान के तेल निर्यात को रोकना है, जिससे वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल के साथ ही भारत सहित दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा संकट मंडरा रहा है. ट्रम्प के आदेश के बाद सोमवार को कई देशों के जहाज होर्मूज में फंसे रहे.

नाकेबंदी का उद्देश्य: ईरान के परमाणु हथियारों के मुद्दे पर तनाव और वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ईरान की तेल बिक्री को पूरी तरह से बंद करना चाहता है.

सैन्य कार्यवाही: अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों को रोका. साथ ही ईरान द्वारा लगाए गए समुद्री खानोंको हटाने का काम भी शुरू किया.

चीन को धमकी: ट्रम्प ने चीन को साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान की सैन्य मदद की, तो अमेरिका उस पर 50 प्रतिशत तक भारी टैरिफ लगा देगा.

ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे : अमेरिका के राष्ट्रति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में शांति वार्ता नाकाम होने के बाद ईरान बातचीत की टेबल पर लौटता है या नहीं. ट्रंप ने एक बार फिर से साफ शब्दों में कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे.

हमारी लड़ाई हर समय जारी है: नेतन्याहू : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपनी शक्ति के शिखर पर है.

भारत से ईरान नहीं लेगा टोल

ईरान ने कहा है कि वह भारत के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने में मदद करेगा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने बताया कि ईरान और भारत के बीच इस मुद्दे पर अच्छी बातचीत चल रही है।उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाव के बावजूद ईरान चाहता है कि भारत के जहाज बिना किसी दिक्कत के इस रास्ते से गुजर सकें। इसलिए ईरान मदद करने के लिए तैयार है। वहीं ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय टैंकरों से टोल लेने की बात से इनकार किया.

अम्बेडकर जयंती पर आज सार्वजनिक अवकाश

भोपाल, 13 अप्रैल. केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को डॉ. बीआर अम्बेडकर की जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी 14 अप्रैल को डॉ. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर पूरे मप्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

वोटर लिस्ट से नाम कटे तो वोट देने का अधिकार नहीं : सुको

नई दिल्ली, 13 अप्रैल. पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रिम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें फिलहाल वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

चीफ जस्टिस सूर्यकान्त और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। यदि ऐसे मतदाताओं को वोट देने की अनुमति दी जाती है, तो इससे उन मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होंगे जिनके नाम अंतिम सूची में शामिल हैं. बेंच ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद और मतदान से कुछ दिन पहले अदालत का हस्तक्षेप चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ऐसे ही लगातार आपत्तियां आती रहीं, तो चुनाव कराना ही मुश्किल हो जाएगा.

एमएसपी तय करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस

नई दिल्ली, 13 अप्रैल. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें सरकार को उचित तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.

महाराष्ट्र के किसान प्रकाश गोपालराव पोहरे, पुरुषोत्तम गावड़े और विशाल ओमप्रकाश रावत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में मांग की गई है कि फसलों पर एमएसपी उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए. इसे तय करते समय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित खेती की वास्तविक लागत (सी2) को प्रभावी महत्व देना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने इन दलीलों पर सुनवाई की. इस दौरान अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यह मुद्दा देश भर के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

फैसला : अलकायदा मॉड्यूल के 3 आतंकी को उम्रकैद की सजा

लखनऊ, 13 अप्रैल. यूपी को दहलाने की साजिश रचने वाले अलकायदा मॉड्यूल के तीन आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सोमवार का एनआईए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. उम्रकैद की सजा वाले तीनों आतंकी अलकायदा के मॉड्यूल अंसार गजवात उल हिंद से जुड़े थे. इन्हें कुकर बम के साथ पकड़ा गया था.

सोमवार को यूपी की एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट ने मिन्हाज, मसरुद्दीन और तौहीद नामक इन तीनों आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मालूम हो कि 11 जुलाई 2021 एटीएस ने दुबग्गा से मिन्हाज को गिरफ्तार किया था. मिन्हाज की निशानदेही पर मसरुद्दीन और तौहीद की गिरफ्तारी हुई थी. मिन्हाज के घर से कुकर बम बरामद हुआ था. जबकि मसरुद्दीन और तौहीद के घर से भी विस्फोटक और पिस्टल बरामद हुई थी. जांच के दौरान पता चला कि ये तीनों 15 अगस्त 2021 को यूपी में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर चुके थे.

तीन हादसों में 24 लोगों की मौत

नई दिल्ली, 13 अप्रैल. रविवार-सोमवार की रात तीन अलग-अलग हादसों में 24 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए. ये हादसे महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में हुए.

महाराष्ट्र के ठाणे में सोमवार को सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई. दो गंभीर घायल हुए हैं. पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10.45 बजे मुर्बाड के गोविली गांव स्थित रैता ब्रिज पर हुआ. कल्याण से मुर्बाड जा रही वैन की सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर ट्रक से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन में सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया. वहीं, गुजरात के सुरेंद्रनगर में सोमवार सुबह लखतर-विरामगाम नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया. हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए. घायलों को सुरेंद्रनगर के अलग-अलग हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. यूपी के हापुड़ में रविवार देर रात 1.30 बजे बारातियों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में 5 बारातियों समेत 6 की मौके पर मौत हो गई. 7 गंभीर हैं. बारात गाजियाबाद के डासना से बुलंदशहर के गुलावठी गई थी. बस में कुल 13 बाराती थे. बाकी दूसरी कारों से पीछे आ रहे थे. शादी के बाद वापस लौटते वक्त बस रोड किनारे खड़ी थी.

महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में दुर्घटनाएं

विनम्र श्रद्धांजलि

स्व. प्रकाशचंद्रजी माहेश्वरी
जन्म : 15-11-1940 महाप्रयाण : 14-4-2005

धर्मयुक्तं सदार्द्र चित्तं पुरुषो कर्म हिते रतः।
इच्छा बुद्धि प्रयासेन भवति प्राण प्रकाशकम।।

जो पुरुष अपने चित्त को सदा भावनामय तथा धर्म युक्त रखते हुए हितकारक कर्मों में लगा रहता है, वह इच्छा, बुद्धि और प्रयास से प्राणों को प्रकाशित करने वाला हो जाता है.

नवभारत Central Chronicle
परिवार

मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक ▶ पांच विभागों की 19,810 करोड़ रुपए की योजना पांच वर्ष तक चलती रहेंगी

सागर जिले की मिडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूरी

2031 तक कृषि विभाग के प्रस्ताव रहेंगे बरकरार

27 गांवों की सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगा लाभ

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 13 अप्रैल. प्रदेश में पांच और विभागों की 19,810 करोड़ की योजनाओं और विकास कार्य अगले पांच वर्ष तक लगातार जारी रहेंगे. कैबिनेट ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजना, महिला बाल विकास के कार्यों, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कृषि विभाग के प्रस्तावों को वर्ष 2031 तक बरकरार रखने की मंजूरी दे दी है.

कैबिनेट ने सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 286 करोड़ 26 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी है. इस परियोजना से सागर जिले की सागर तहसील के 27 गांवों की 7200 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए किसानों को लाभ मिलेगा. वहीं प्रदेश में 8 नए वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति भी दी गई है. मैहर, मउगंज, पांढुर्णा, धार में मनावर और पीथमपुर, इंदौर में लसूडिया और सांवेर एवं झाबुआ में पेटलावद में नये वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जाएगा.

इसी तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्याह्न भोजन सहित कई योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. प्रदेश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के माध्यम से कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने, नरवाई प्रबंधन को बढ़ावा देने और प्रदेश के वन पट्टाधारियों के लिए हस्तचलित/बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए योजना भी अगले पांच वर्ष तक चलती रहेगी. इसके लिए 2,250 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. वहीं प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को आगामी 5 वर्षों तक चलाए जाने के लिए 1,674 करोड़ की स्वीकृति दी गई. इसमें जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय से समबद्ध किया जाएगा. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने के लिए लगभग 1,005 करोड़ खर्च होंगे. महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं महिला हेल्पलाइन-181 योजना के संचालन के लिए 240 करोड़ 42 लाख और आगामी 5 वर्ष, 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक संचालन एवं निरंतरता की स्वीकृति दी गई है.

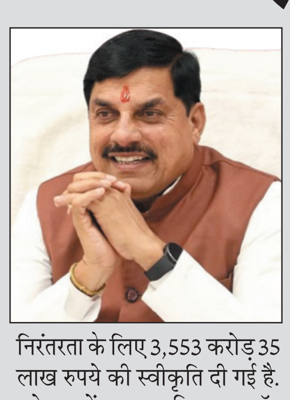

निर्णय के तहत लोक निर्माण के तहत अलग-अलग विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. इसके तहत बीओटी मार्गों का विकास एवं पर्यवेक्षण के लिए 150 करोड़, बीओटी परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए 765 करोड़, एन्यूटी भुगतान के लिए 4,564 करोड़ और म.प्र. सड़क विकास निगम के लिए 5,322 करोड़ की स्वीकृति सहित 16वें वित्त आयोग की अवधि एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखे जाने की स्वीकृति दी गई है.